श्री दिन्शा जे. पटेल: सभापति जी, माननीय सदस्य जो बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमारी प्राइम मिनिस्टर के साथ भी बात हुई और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक Special Task Force यानी एक High Powered Committee का गठन किया और गठन के बाद उस कमेटी ने अपनी सारी रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को दे दी है। उस रिपोर्ट में दूसरे डिपार्टमेंट भी शामिल हैं, फाइनेंस भी शामिल है, लेबर भी शामिल है, कई दूसरे डिपार्टमेंट्स भी जुड़े हुए हैं और उनको यह रिपोर्ट भेज दी गई है। माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि ऋण देने में बैंक देरी करते हैं, तो वह देरी कैसे कम हो सके और जल्दी से जल्दी उनको लोन कैसे मिल सके, यह बात भी इसमें बताई गई है। इस बारे में फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ भी हमारा डिस्कशन हुआ है। जब इस रिपोर्ट पर अमल होगा, तो अमल के लिए भी एक time bound programme बना दिया गया है, किसी डिपार्टमेंट को 2 महीने, किसी डिपार्टमेंट को 3 महीने, किसी डिपार्टमेंट को 6 महीने का समय दिया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में वह काम होना चाहिए। जहां तक इसकी मॉनीटरिंग का सवाल है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपनी अध्यक्षता में मॉनीटरिंग करने का फैसला किया है, जिससे यह दिक्कत कम हो जाएगी।

श्री श्रीगोपाल व्यास: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि केरल में जो ऋण माफी के लिए कहा गया है, क्या आपको मालूम है कि उनकी संख्या क्या है और कितने लोगों की ऋण माफी के लिए कहा गया है?

श्री दिन्शा जे. पटेल: सभापति जी, मैंने यही बताया है कि केरल के लिए करीब 72 करोड़ रुपए की ऋण माफी की बात है, लेकिन यह अकेले केरल का सवाल नहीं है ....(व्यवधान)... वही मैं बता रहा हूं कि यह सारे देश की इकाइयों की प्रॉब्लम है। इसीलिए सारे देश का जो आंकड़ा है, वह प्राप्त करके, उसमें क्या हो सकता है, इसकी जानकारी के लिए एक उच्च अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद उसमें क्या हेल्प हो सकती है, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि यह sub judice हो गया है, आन्ध्र और तमिलनाडु में केस कोर्ट में भी गया है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि सारा गठित करके, सारा विचार करके इसके बारे में सोचेंगे।

Procurement of wheat

*226. SHRI NAND KUMAR SAI: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government has taken any measures during the Rabi marketing season 2009-10 to increase procurement of wheat in various major wheat producing States;

(b) if so, the details thereof;

(c) the extent to which procurement of wheat has been increased in each of such major wheat producing States as compared to previous year, State-wise;

(d) whether Government has also allowed NAFED and other Government agencies to purchase wheat for the Central Pool;

(e) if so, the details thereof; and

(f) the quantity of wheat procured by such agencies in the current season so far?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (f) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The following measures were taken by Government to increase procurement of wheat during the Rabi marketing season (RMS) 2009-10:-

(i) Minimum Support Price (MSP) was increased from Rs. 1000 per quintal in Rabi Marketing Season (RMS) 2008-09 to Rs. 1080 per quintal in RMS 2009-10.

(ii) State Governments were requested to make necessary arrangements to ensure opening and effective functioning of adequate number of procurement centres, so that farmers can get the benefit of MSP. Arrangements for procurement were reviewed with the State Governments from time to time.

(iii) Ban on export of wheat was continued in 2009-10 also to ensure availability of wheat.

(c) Details showing procurement of wheat in RMS 2007-08, 2008-09 and 2009-10 in major wheat-producing States is given in the Statement-I (*See* below).

(d) and (e) The State Governments can engage as Government Agencies and cooperatives for procurement of wheat for Central Pool. Agencywise procurement of wheat during 2009-10 is given in the Statement-II (*See* below).

(f) The procurement of wheat in major wheat-producing States in RMS 2010-11 will commence from 1st April, 2010.

Statement-I

Procurement of wheat in major producing States

(in lakh tonnes)

State	RMS 2007-08	2008-09	2009-10
Punjab	67.57	99.41	107.25
Haryana	33.46	52.37	69.24
Uttar Pradesh	5.49	31.38	38.82
Rajasthan	3.84	9.35	11.52
Madhya Pradesh	0.57	24.10	19.68
Others	0.35	10.28	7.31
Total	111.28	226.89	253.82

Statement-II

Agency-wise procurement of wheat during Rabi marketing season 2009-10

(in lakh tonnes)

Food Corporation of India	47.88
State Governments	46.90
Civil Supplies Corporation	35.35
Cooperatives	67.82
CONFED	6.32
AGRO Corporation	22.01
State Warehousing Corporations	20.54
State Food Corporations	2.91
UP Upbhokta Sahkari Sangh (UPSS)	4.09
Total	253.82

श्री नन्द कुमार साय: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार सामान्यत: गेहूं खरीदने के बाद उसे उन मिलों को बेचती है, जो आटा बना करके उपभोक्ताओं को बेचते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप गेहूं किस दर पर आटा बनाने वाले उन एजेंसियों/मिलों को बेचते हैं और वे आटा बनाकर उपभोक्ताओं को किस दर पर बेचते हैं?

PROF. K.V. THOMAS: Sir, there are two OMS, that is, Open Market Sales. In the OMSs we decide higher price for bulk consumers, which is more than the MSP, and on that price they have to bid. Every year, depending on the availability, we decide and declare OMSs price for the bulk consumers. In the case of States, we give wheat at the OMS price to the States. The State Governments can make use of that wheat and supply either through the TPDS or the Civil Supplies Corporation.

श्री सभापति : आप दूसरा प्रश्न पूछिए।

श्री नन्द कुमार साय: माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का तो उत्तर ही नहीं आया। मैं माननीय मंत्री श्री शरद पवार जी ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: सवाल पूछने दीजिए ...(**व्यवधान**)...

श्री कलराज मिश्र: सभापति महोदय, जो प्रश्न पूछा जाए ...(**व्यवधान**)... गलत या सही, उसका जवाब तो आना चाहिए ...(**व्यवधान**)... जवाब उसके संबंध में आना चाहिए ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: ठीक है। Let us hear the question. ...*(Interruptions)*...

श्री नन्द कुमार साय: सभापति महोदय, मैंने साफ-साफ पूछा था कि ...(**व्यवधान**)... महोदय, इसको पहला ही सवाल माना जाए ...(**व्यवधान**)... आप उन्हें किस दर पर देते हैं और वे आटा बनाकर उपभोक्ताओं को किस दर पर बेचते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : ठीक है, ठीक है।

श्री शरद पवार: यह जो फ्लोर मिल्स के बारे में जो गेहूं की बिक्री हम लोग करते हैं, इसमें किसी फ्लोर मिल को subsidised rate पर allotment नहीं किया जाता है। जब ओपन मार्केट में हम माल इन लोगों के लिए बेचते हैं, तब हम इनकी तरफ से ओपन टेण्डर मांगते हैं और टेण्डर्स में जो बिल्डर्स high price वाला होता है, उसी को माल दिया जाता है। बाद में वह प्रोसेस करके इसका रवा, आटा ओपन मार्केट में बेचता है। इसके ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं है।

श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला: सर ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : आप बीच में दखल मत दीजिए, रूपाला जी, कृपया आप बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)... वह आपका सवाल नहीं है ...(**व्यवधान**)...

श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला: सर, सरकार किसानों से गेहूं खरीदती है ...(**व्यवधान**)... वह किस दर पर बेचती है, यह जानने का हक नहीं है? ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : यह आपका सवाल नहीं है ...(**व्यवधान**)...

श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला: सर, इसमें मुझे आपकी सुरक्षा चाहिए ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : गलत काम में आपको कोई सुरक्षा नहीं दे सकता है ...(**व्यवधान**)... आपके साथी सवाल पूछ रहे हैं, उनको पूछने दीजिए ...(**व्यवधान**)...

श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपाला: सर, किसान मारा जाएगा ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : कृपया आप लोग बैठ जाइए। आप दूसरा सवाल पूछिए।

श्री नन्द कुमार साय: माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि देश की आबादी बढ़ रही है और उसके हिसाब से आपको अपना बफर स्टॉक भी बढ़ाना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपने इस समय आबादी के हिसाब से अपना स्टॉक बढ़ाया है? अगर बढ़ाया है, तो कितना बढ़ाया है और उसके रखरखाव के लिए क्या प्रबंधन है, क्योंकि बहुत जगह गेहूं सड़ जाता है, वह बाहर पड़ा रहता है, उसके रखरखाव के लिए आपने क्या व्यवस्था की है?

श्री शरद पवार: हर महीने में बफर स्टॉक के कुछ norms होते हैं और इन norms के मुताबिक हम बफर स्टॉक रखते हैं, मगर देश की आबादी देखने के बाद बफर स्टॉक के साथ-साथ हमने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है और इसके मुताबिक हम "Strategic Reserve" के नाम से अलग तरह का गेहूं रखते हैं। जहां तक आज देश की स्थिति है, देश में बफर स्टॉक के जो norms हैं, उसके आसपास स्टॉक आज देश में रखा हुआ है।

DR. JANARDHAN WAGHMARE: Sir, I would like to know the States from where they get maximum procurement of wheat and rice, and what the position of procurement this year would be.

SHRI SHARAD PAWAR: Punjab is a State from where we have maximum procurement. Practically, we have reached more than 100 lakh tonnes. For this year, we, recently, called a meeting of all the Secretaries of the Agriculture Department and the Food Department of various States. And, from the information which we have got from them, our expectation is that we will be able to procure 260 lakh tonnes as against the last year's procurement of 253 lakh tonnes. So, this year, the position is better than the last year.

डा. राम प्रकाश: सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मिलों को टेंडर के हिसाब से, जिसका सबसे ज्यादा महंगा होगा, अनाज बेचा जाएगा, तो महंगाई बढ़ेगी। सरकार को, गेहूं का जो maximum या minimum price है, उसके हिसाब से भाव तय करना चाहिए और फिर आगे बेचना चाहिए, मिलों को देना चाहिए। अगर highest tender के हिसाब से देंगे, तो आटा और ज्यादा महंगा बिकेगा, इसलिए महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए हमें उसका एक fixed rate रखना चाहिए। जिस भाव गेहूं खरीदा गया है और जिस भाव मिल को देना है, दोनों में कोई निश्चित अंतर होना चाहिए।

श्री शरद पवार: जहां तक ये flour mills हैं, वे मार्केट से गेहूं खरीदने के बाद fixed rate से आटा, रवा बेचेंगे, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए उनको सस्ता या subsidized देने से यह विश्वास नहीं होता कि यह आम जनता को भी subsidized मिलेगा ...(**व्यवधान**)...

डा. राम प्रकाश: मैंने subsidized के लिए कहा ही नहीं है।

श्री शरद पवार: इसमें दूसरा एक रास्ता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स Public Distribution System से रवा आटा का distribution करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए अलग तरह का allotment देकर कीमत पर रोक लगाने की कोशिश होगी, तो इसमें भारत सरकार सहयोग देगी।

SHRI MOINUL HASSAN: Sir, in Annexure II of the reply, the Agency-wise procurement of wheat of the previous Rabi season, namely, 2009-10, has been shown. So far as the Food Corporation of India is concerned, the procurement of FCI, as compared to Co-operatives, has been quite less. Actually, the FCI is not procuring wheat from the ultimate sellers at the right time. This puts the sellers in trouble and they end up going in for distress sale, I would like to know from the hon. Minister whether he would direct the FCI to go to the mandi at the right time, for the purchase of wheat or any other crop from the ultimate seller, that is, the farmers of the country.

SHRI SHARAD PAWAR: Generally, in the market, the arrival of wheat is somewhat in the first week of March, and we, immediately, start the procurement. But it is, practically, difficult for FCI to set up Purchase Centres in each and every mandi of the wheat producing States. That is why this responsibility has been given to States. The State Government is procuring it; the State corporations are procuring it. That State Governments are using their cooperative institutions which are also appointed as agents and they are procuring it. So, there are a number of organizations which are coming forward on behalf of the State Governments; they procure it; they handle it with the FCI.

MR. CHAIRMAN: Thank you. Question Hour is over.